श्री रवि शंकर प्रसादः सर, यह बहुत गंभीर मामला है ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अब आप इसको छोडिये । ...(**व्यवधान**)... ऐसे नहीं होगा। आपका नाम मेरे पास नहीं आया है, फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः सर, मंत्री भी बिहार से है, सरकार भी बिहार से है ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये ।...(**व्यवधान**)... आप पहले बैठिये। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर आकर बोलिए ।...(**व्यवधान**)... नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती सविता शारदा । ...(**व्यवधान**)... ठीक है। मैं देख रहा हूं। श्रीमती सविता शारदा ।...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवानः सर, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैंने जैसा कहा कि प्रिवियस गवर्नमेंट ने यदि दाम तय कर दिये होते, तो एमओपी का, पोटाश का आयात उसी समय हो गया होता। हमने 22 मई को कार्यभार ग्रहण किया । उस समय मार्च तक डिपार्टमेंट ने या सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया । जब हमारे पास फाइल आई तो उसका जो मूल्य था वह 124 डालर से बढ़कर 180 डालर हो गया था। उस पर हमारे साइन की आवश्यकता थी और यह हमारे लिए बहुत डिफीकल्ट काम था। मैं अपैइ इमेज पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहता था, इसके कारण विलम्ब हुआ, प्रिवियस गवर्नमेंट की गलती के कारण विलम्ब हुआ ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : श्रीमती सविता शारदा ।...(**व्यवधान**)...

डा0 छत्रपाल सिंह लोढाः प्रीवियस गवर्नमेंट की गलती के कारण नहीं हुआ ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठिएय, छत्रपाल सिंह जी, बैठिये । ...(**व्यवधान**)... बैठिये। आप बोलिये ।

इंटरनेट के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करना

*368. **श्रीमती सविता शारदाः** क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में ठेका प्रथा के कारण हो रहे अपराधों को ध्यान में रखते हुए सरकार का इंटरनेट के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर0वेलू): (क) से(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है

विवरण

(क) जी हां, खरीद प्रक्रिया में लगने वाले समय में कटौती करके, पारदर्शिता लाने, कुशलता में सुधार लाने तथा मांग पत्र भेजने वालों को बेहतर सेवा मुहैया कराने सहित वस्तुसूची पर बेहतर नियंत्रण लाने के लिए रेलवे द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रोक्योरमेंट अथवा ई-प्रोक्योरमेंट की एक प्रणाली विकसित की जा रही है, इस प्रणाली से निर्माण संबंधी निविदाओं में माफिया/आपराधिक गातिविधियों में कमी आने की भी संभावना है ।

(ख) इलैक्ट्रानिक प्रोक्योरमेंट की उत्तर रेलवे में एक पायलट परियोजना प्रारंभ की जा रही है। इस पायलट परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और उससे प्राप्त अनुअव के आधाअर पर इसे और बेहतर करने के पश्चात् इस प्रणाली का अन्य क्षेत्रीय रेलों तक विस्तार किआ जाएगा। इस प्रणाली में भंडारों की खरीद, निर्माण, सेवाएं और सामग्रियों की बिक्री जैसी गति-विधियां शामिल की जाएंगी ।

(ग) प्रयोग के तौर पर, इलैक्ट्रॉनिक प्रओक्योरमेंत प्रणाली को प्रांरभ करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है, जिसके लिए 2004-05 के रेलवे बजट में आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की मांग की गई है ।

Inviting tenders through internet

†*368. SHRIMATI SAVITA SHARDA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to invite tenders through internet keeping in view the crimes being committed due to the contractor system in railways;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when a final decision is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI R. VELU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. A system of electronic procurement of E-Procurement is being developed by the Railways to bring about transparency, improved

† Original notice of the question was received in Hindi.

efficiency by reduction in procurement time cycle and better control on inventory along with improved service level tc indentors. The system is also expected to curtail mafia/criminal activities seen in works tenders.

(b) A pilot project on Electronic Procurement is being started in Northern Railway. After successful implementation of this pilot project and fine-tuning of the system on the basis of working experience, the system would be extended to other Zonal Railways. The system would cover all activities like procurement of stores, works,services and sale of materials.

(c) The decision to start an Electronic Procurement system on trial basis has already been taken for which necessary sanction of funds has been sought in the Railway Budget, 2004-05.

श्रीमती सविता शारदाः धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, ठेका प्रथा के कारण दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के बढ़ने के कारण काफी संख्या में अपराधों की बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके साथ ही साथ कई बार मर्डर भी हो रहे है। अभी पिछले दिनों में बिहार जाते हुए दो लोगों का मर्डर हो गया है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें बताया है कि इसके लिए मांग पत्र भेजने वालों को बेहतर सेवा मुहैया कराने वालों के लिए इलेक्ट्रानिक प्रोक्योरमेंट अथवा ई-प्रोक्योरेमेंट की प्रणाली विकसित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इस प्रणाली का कब तक विकास होगा? मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रणाली से निर्माण संबंधी निविदाओं में आपराधिक गातिविधियों में कमी आयेगी, इसके बारे में, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कितनी संख्या में इन गातिविधियों में कमी आयेगी?

SHRI R. VELU. Sir, the hon. Member knows that this system was announced by the hon. Minister of Railways in this Budget. We are now working on the system as a pilot project in the Northern Railways. Since we are putting it as a pilot project, we are working on the model and our operating capacity. It will take at least two years to complete the whole system. As the hon. Member has mentioned, I totally agree with her that mafia groups really do all sorts of mischief in terms of submission of tenders, getting contracts, etc. Toget over this, we are going to have this system of electronic procurement not only for contracts but also for procurement of store materials, which will go a long way to ensure that there is efficiency in the system, so that the procurement time is reduced, the cost is reduced, and we get all the benefits.

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि तीन साल तक इसमें होगा। मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत देर हो जायेगी, क्योंकि अपराधों की संख्या दिन-प्रति –दिन

बढ़ रही है, इसको देखते हुए तीन साल तक रोकना बहुत मुश्किल काम है। इसमें मुझे लगता है कि भले ही कार पार्किंग हो । इन्होंने दो-तीन वस्तुओं के बारे में बताया है-प्रणाली में भंडारों की खरीद है, निर्माण-कार्य है, अलग-अलग तरह की सेवाएं है, पार्स्ल योजना है, यहां तक कि वहां पर रेलवे के जो पार्सल भेजे जाते है, उसमें जो ठेका प्रथा दी जाती है, उसमें भी काफी भ्रष्टाचार है। तो मंत्री जी, अगर तीन साल तक करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत काम आगे बढ़ जाएगा। यह तीन साल से कम समय होना चाहिए ।

जो मेरा तीसरा प्रश्न था "ग" कि इस संबंध में अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा, तो आपने उत्तर में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट प्रणाली को प्रारंभ करने का निर्णय पहले से लिया गया है। पहले से यानि कब से लिया गया है। यह आपने नहीं बताया है । वर्ष 2004-2005 रेलवे बजट में आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की मांग की गई है, तो कितनी धनराशि आप आवंटित करेंगे और कब तक करेंगे?

श्री सभापतिः ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछ लिए है ।

SHRIR. VELU: Well, we will try to expedite matters. I never said three years; I said two years. Now, the hon. Member has suggested that matters should be expedited. We have already approved Rs. 3.25 crores and provided Rs. 1.75 crores in the Budget for this and, if necessary, additional funds will also be provided. The only point is that this being a pilot project, we will try to work out a sound system so that we have our own system, so that Railways have their own E-procurement system. So, the borrowing system will be restricted till the time we develop our own system as such. We appreciate the feelings of hon. members. We will try to expedite matters. And we will shorten the period of two years; we will make it less than two years.

*369. [The Questioner (SHRI R.P. GOENKA) was absent. For answer *vide* page 39 *infra.]*

Loan licenses for Drugs

*370. SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: †
SHRIMATI PREMACARIAPPA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of loan licenses for drugs that have been issued in the country for manufacture of medicines;

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Digram Pal Sabharwal.